रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1965 (वैसाख 4, 1887)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 1965 (VAISAKHA 4, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 7 अप्रैल 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 7th April 1965 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
39	No. 23-ITC(PN)/65, dt. 6th April, 1965.	Ministry of Commerce.	Import of fresh fruits from Pakistan under the terms of Protocol No. II to the Trade Agreement between India and Pakistan —April 1965 -March 1966.
40	No. 24-ITC(PN)/65, dt. 8th April, 1965.	Do.	Import of Raw materials/ components —Conversion of a part of the licence for import of iron and steel items.
41	No. Ind-3(24)/64, dt. 7th April, 1965.	Min. of Steel and Mines.	Decision to set up a Technical Committee to make a rational assessment of the capacity of the re-rolling mills.
	सं० इन्डस्ट्री-3(24)/64, दि० 7 अप्रैल 1965	इस्पात और खान मंत्रालय	पुनर्वेलन मिलों की क्षमता का तर्क संगत मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी समिति स्थापित करना ।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची
CONTENTS

	पृष्ठ Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	231
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	315
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	201
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

	पृष्ठ Pages
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	657
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं ..	1359
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश ..	105
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	249
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें .	141
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	29
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	2381
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	89
पूरक सं० 17—	
17 अप्रैल, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	543
27 मार्च, 1965 को समाप्त होनेवाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	555

	Pages
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	231
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	315
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	201
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories —	657
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories	1359
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	105
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	249
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	141
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	29
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2381
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	89
SUPPLEMENT No. 17—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 17th April 1965	543
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 27th March 1965	555

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 1965

सं० 29-प्रेज/65—परिशिष्ट—शनिवार दिनांक, 12 दिसम्बर 1964 को प्रकाशित हुए भारतीय राजपत्र के भाग I, अनुभाग 1 में अधिसूचित इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 84–प्रेज/64, दिनांक 4 दिसम्बर 1964 में प्रादेशिक सेना विभूषण तथा प्रादेशिक सेना मैडल के अध्यादेशों के सम्बन्ध में निम्नांकित सुधार किये गये हैं :—

प्रादेशिक सेना विभूषण

"छठी" धारा के उप-पैरा (ख) के पश्चात् निम्न उप-पैरा (ग) **जोड़िये** —

"(ग) अक्तूबर, 1962 से घोषित आपतकाल के बीच भारत में प्रादेशिक सेना कमीशन प्राप्त अधिकारी की अंगीभूत सेवा।"

प्रादेशिक सेना मैडल

"सातवीं" धारा के उप-पैरा (ख) के पश्चात् निम्न उप-पैरा (ग) **जोड़िये** :—

"(ग) अक्तूबर, 1962 से घोषित आपतकाल के बीच भारत में अंगीभूत सेवा।"

ए० व० होप्क्रॉफ्ट, अवर सचिव

योजना आयोग

शिक्षा प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1965

विषय : **शिक्षा सम्बन्धी पैनल का पुनर्गठन।**

सं० 1/4/63-शिक्षा—भारत सरकार सहर्ष यह सूचित करती है कि इस संकल्प के जारी होने की तिथि से मेटल वर्क्स कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड के श्री एच० के० एस० लिंडसे शिक्षा सम्बन्धी पैनल में मनोनीत किये जाते हैं।

2. एसोशिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स आफ इंडिया, एंड्रयूले कोल लिमिटेड, 8-क्लाइव रोड, कलकत्ता-1 (पश्चिमी बंगाल), जिन्हें योजना आयोग के संकल्प सं० 1/4/62-शिक्षा, दिनांक 25 मई 1964 में शिक्षा पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था, 19 फरवरी, 1965 से पैनल के सदस्य नहीं रहे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के गजट में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति शिक्षा सम्बन्धी पैनल के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, मंत्री-मंडल सचिवालय, संसद कार्य विभाग, और प्रधान मंत्री सचिवालय को भेज दी जाए।

दया कृष्ण मल्होत्रा, संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 1965

सं० 3(1)/65-बी०ओ०टी०—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 3(1)/64-बी० ओ० टी०, दिनांक 6 जुलाई 1964 जो कि क्रमशः संकल्प सं० 3(1)/64-बी० ओ० टी० दिनांक 7 अगस्त 1964 और 19 अक्तूबर 1964 द्वारा संशोधित किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने निश्चय किया है कि व्यापार बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या 24 से बढ़ाकर 26 कर दी जाये तथा निम्नलिखित संसद सदस्यों को उक्त बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया जाए :—

1. श्री पत्तम पिल्ली गोविन्दा मेनन,
2. श्री राधेश्याम रामकुमार मोरारका, और
3. बाबूभाई चिनाय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, प्रधान मन्त्री सचिवालय, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और भारत के सभी राज्यों की सरकारों को भेजी जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

डी० एस० जोशी, सचिव

खाद्य और कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 12 अप्रैल 1965

सं० 10-3/65-काम० II—भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय के संस्ताव संख्या एफ० 43-11/48-काम०, दिनांक 21 मई 1949 (जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया) की धारा 3(i) के द्वारा दिये गये अधिकार का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने डा० एम० एस० रन्धावा, महानिदेशक, गहन कृषि क्षेत्र और भारत सरकार के विशेष सचिव, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) और उप-प्रधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, को 3 अप्रैल 1965 (अपराह्न) से श्री ए० डी० पंडित के स्थान पर, भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के प्रधान के रूप में मनोनीत किया है।

निर्मलकुमार दत्ता, अवर सचिव

परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

पत्तन

संस्ताव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 1965

सं० 9-पी० जी० (11)/65—भारत सरकार को 1963-64 की कलकत्ता पत्तन की प्रशासनिक रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशिष्टियां निम्न हैं :—

1. **वित्तीय स्थिति**—विचाराधीन वर्ष में पोर्ट कमिश्नर की राजस्व प्राप्ति 1,771.83 लाख रुपया रही जबकि इसके विपरीत

पिछले वर्ष में यह राशि 1,696.98 लाख रुपया थी। राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी मुख्यत: सम्पूर्ण यातायात में लगभग 7 प्र० श० की बढ़ोतरी के कारण हुई।

इस वर्ष व्यय में 1,719.09 लाख रुपये लगे। इसके विपरीत पिछले वर्ष यह संख्या 1,644.71 लाख रुपया थी। राजस्व लेखा में 52.73 लाख रुपये के अधिशेष से वर्ष समाप्त हुआ। व्यय में बढ़ोतरी मुख्यत: इन कारणों से हुई, सिब्बन्दी, स्टोर श्रमप्रभार और बिजली में अधिक व्यय।

वर्ष के अन्त में राजस्व अधिशेष लेखा में विनियोग के लिये उपलब्ध राशि, जो इस वर्ष के अधिशेष और पिछले वर्ष से आगे लाये हुए शेष की कुल जोड़ थी, 53.18 लाख रुपया थी। इस राशि में से राजस्व के लिये अंशदान के रूप में पूंजी लेखा के लिये 53 लाख रुपये की राशि विनियोजित की गई, और शेष अगले वर्ष के लिये ले जाई गई।

इसके अतिरिक्त पूंजीगत निर्माण कार्यों की वित्तीय सहायता के लिये इस वर्ष सरकार से कमिश्नर ने 100 लाख रुपये और विश्व बैंक से विदेशी मुद्रा में 310 लाख रुपये उधार लिये और 30 वर्षों के लिये 5 प्र० श० पर 100 लाख रुपये का ऋण जारी किया।

विभिन्न राजस्व आरक्षित निधियों में 31 मार्च 1964 को सम्पूर्ण अधिशेष 834.71 लाख रुपया था।

2. **यातायात**—इस वर्ष पत्तन से जाने वाला संपूर्ण आयात और निर्यात क्रमश: 6.028 मिलियन टन और 4.91 मिलियन टन था। 1962-63 में आयात और निर्यात संख्यायें क्रमश: 5.48 मिलियन टन और 4.723 मिलियन टन थीं।

1962-63 तथा 1963-64 में आने जाने वाले महत्वपूर्ण सामानों का आयात और निर्यात टन भार नीचे दिया जाता है।

माल	1962–63 (मिलियन टन)	1963–64 (मिलियन टन)
आयात		
खाद्यान्न . . .	1.083	1.553
नमक . . .	0.408	0.396
निर्यात		
कोयला . . .	2.151	1.974
गनी . . .	1.078	1.104
चाय . . .	0.182	0.163
कच्ची धातु . . .	0.550	0.790

3. **पत्तन रेल**—इस वर्ष रेल से प्राप्त आमदनी 234.36 लाख रुपया रही। इसके विपरीत पिछले वर्ष यह संख्या 249.82 लाख रुपया थी। इसमें लगभग 30 लाख रुपये की राशि भी शामिल है जो 31 मार्च 1962 तक के लिये ट्रंक रेलवे से सीमान्त प्रभार के बकाया के रूप में प्राप्त हुई थी।

4. **यात्री यातायात**—इस वर्ष पत्तन से जहाज पर चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या 9,007 थी। उतरने वाले यात्रियों की संख्या 4,414 थी। 1962-63 में ये संख्यायें 10,923 और 8,942 थीं।

5. **चोरी**—1959-60 में पत्तन में चोरी की घटनाओं को कम करने के लिये लागू किये गये विभिन्न उपाय सक्रिय रहे।

6. **जहाजरानी**—इस वर्ष पत्तन में आने वाले जहाजों की संख्या 1,828 थी। पिछले वर्ष यह संख्या 1,821 थी। पत्तन में आने वाला सब से अधिक डुबाव का जहाज एस० एस० वेलेजली विक्टरी था जो आगे और पीछे 27-3 ड्रा करता था और सब से अधिक डुबाव का पत्तन से जाने वाला जहाज एस० एस० जनूवा था जो आगे और पीछे 23 फीट और 9 इंच ड्रा करता था।

पिछली लदान संख्याओं को दृष्टि में रखते हुए अतिरिक्त यातायात के अनुसार जहाजों की संख्या में जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिये थी इस वर्ष बढ़ोतरी उससे कम रही। यह इस वर्ष डुबाव में सुधार के कारण हुआ जिसके कारण जहाज अधिक माल ले जा सके। पिछले वर्ष की अपेक्षा पत्तन तक के नौवहन नदी मार्ग में दांडे की दशायें सामान्यतया अच्छी रहीं। इस वर्ष जहाज के डुबाव को नियंत्रण में रखने वाला शामिल दांडा 140 दिनों तक डायमंड बन्दरगाह (बलारी बार) के नीचे रहा और 226 दिनों तक डाइमंड बन्दरगाह के ऊपर।

निकर्षण, जिसके अन्तर्गत नौवहन जलमार्ग घाटों, जलपाश प्रवेशमार्ग और गोदी क्षेत्र का निकर्षण शामिल है, पर सम्पूर्ण व्यय 146.1 लाख रुपये का हुआ। इसके विपरीत पिछले वर्ष यह संख्या 156.1 लाख रुपया थी।

7. **हल्दिया लंगरगाह**—नवम्बर, 1963 से फरवरी, 1964 तक अच्छी ऋतु में लगातार पांचवें वर्ष में भी खाद्यान्न आयात करने वाले जहाजों ने हल्दिया लंगरगाह में माल उतारा। 1963-64 में कुल मिलाकर 15 खाद्यान्न के जहाजों ने माल उतारा। लंगरगाह को इस्तेमाल करने वाला सब से अधिक डुबाव वाला जहाज एस० एस० "आलिव बैंक" था जिसका डुबाव 29 फीट 10 इंच का था। लंगरगाह पर सब मिला कर 60,414 टन खाद्यान्न उतारा गया।

8. **नदी माडल प्रयोग**—तकनीकी उपकरणों के सब सामान जिनका क्रय आदेश दिया गया था मिल गये है और इस्तेमाल किये जा रहे हैं। अनुसन्धान जहाज अनुसन्धानी जो यू० के० में बनाया गया था व्यवहृत किया जा रहा है। व्यवस्थित आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पूना के केन्द्रीय जल और बिजली अनुसन्धान केन्द्र के आदर्श पर अध्ययन किया जा रहा है। 1963-64 में जो मुख्य प्रयोग किये गये वे ये हैं :—

(1) नीलन, नूरपुर, पूर्वी गुट और मोयापुर बारों के सुधार के लिये औचित्य अध्ययन।

(2) हुगली नदी के ऊपर प्रस्तावित पारक से संबद्ध प्रयोग।

9. **श्रम**—इस वर्ष पत्तन में श्रम स्थिति सन्तोषजनक रही। खाद्यान्न के अतिरिक्त सामान्य आयात की प्रति जहाज प्रतिदिन निकासी की औसत दर 434 टन थी। पिछले वर्ष यह संख्या 445 टन थी। आयात किये खाद्यान्न के मामले में प्रति जहाज प्रतिदिन की निकासी 1,040 टन थी। पिछले वर्ष यह संख्या 1,372 टन थी। जहाजों पर मजदूरों द्वारा निकासी कार्य बढ़ाने के लिये एक उत्प्रेरक योजना लागू करने का प्रश्न कलकत्ता गोदी श्रम मंडल के विचाराधीन है। सामान्य निर्यात, जिसमें कोयला और धातु शामिल नहीं है, के मामले में प्रति जहाज प्रतिदिन लदान की औसत दर 642 टन थी। पिछले वर्ष यह संख्या 526 टन थी।

कोयला निर्यात के मामले में प्रति जहाज प्रतिदिन की औसत लदान दर 1,036 टन थी। पिछले वर्ष यह संख्या 1,110.3 टन थी। धातु के जहाजों के मामले में लदान की प्रतिदिन औसत दर 1,511 टन थी। पिछले वर्ष यह संख्या 1,306 टन थी। पारगमन छादनों और यार्डों में उपलब्ध स्थान का इस वर्ष पूरा उपयोग किया गया। पत्तन में किसी भी समय अत्यधिक जमाव नहीं हुआ सिवाय इसके कि विशेष प्रकार के रेल के डिब्बों के मिलने में कठिनाई के कारण और आयात करने वालों तथा निकासी एजेन्टों द्वारा कागजात पेश करने में देरी के कारण हैवीलिफ्ट यार्डों में माल जमा हो गया था।

10. **हुगली कनहार**—इस वर्ष कनहार से 56.20 लाख रुपये की आमदनी हुई और व्यय 43.59 लाख रुपया हुआ। 12.61 लाख रुपया अधिशेष रहा।

11. **पत्तन विकास**—इस वर्ष जो पूंजीगत निर्माण कार्य प्रगति पर थे उन पर 575.54 लाख रुपया व्यय हुआ। इस वर्ष विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर पर्याप्त प्रगति हुई। इसके अन्तर्गत पत्तन जहाजों का निर्माण जैसे एक प्रेषण जहाज, एक अग्निशामक जहाज, तीन जलावतरण, एक ग्राह-निकर्षक, दो चिखलबजरे, दो जलनौका, दो मार्गदर्शी जहाज और एक सर्वेक्षण जहाज शामिल हैं। विचाराधीन वर्ष में हल्दिया की नई गोदी योजना के निर्माण के लिये भूमि प्राप्ति का कार्य भी प्रगति पर रहा और परियोजना से सम्बन्धित कुछ प्रारम्भिक कार्य भी हाथ में लिये गये।

12. **विविध**—इस वर्ष विश्व बैंक की सहायता और प्रोत्साहन से स्थापित किये गये नये द्रविक अध्ययन विभाग ने कई अन्वेषण किये।

13. **सराहना**—विचाराधीन वर्ष में पोर्ट कमिश्नर ने कठिन दशाओं के होते हुए भी उपयोगी कार्यों का एक और वर्ष पूरा किया। सरकार उनके कार्य की सराहना करती है।

नरेन्द्र पाल माथुर, सह-सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 19 अप्रैल 1965

सं० 41/9/63—एडवर्टाइजिंग—सूचना और प्रसारण मंत्रालय का विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार की नीतियों और कार्यों के प्रचार के लिए दृश्य प्रचार सामग्री तैयार करता है। वह प्रदर्शनियां लगाता है और विज्ञापन पोस्टर, फोल्डर, ब्राड-शीट, केलैंडर डायरी, सिनेमा स्लाइड, होर्डिंग, धातु की तख्तियों आदि द्वारा प्रचार कार्य करता है। भारत सरकार का विचार है कि विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के कार्यों के बारे में, इस विषय के अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्तियों और संगठनों से सलाह मशविरे की व्यवस्था लाभदायक होगी। तदनुसार केन्द्रीय विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार सलाहकार समिति को फिर से स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्री और उपाध्यक्ष सूचना और प्रसारण उप-मंत्री होंगे।

2. उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है :—

1. एडवर्टाइजिंग एजेन्सीज़ एसोसिएशन आफ इंडिया, बम्बई के अध्यक्ष।
2. श्री बी० बी० मुंडकर, मालिक, उल्का एडवर्टाइजिंग, बम्बई।
3. श्री पी० एन० शर्मा, संचालक एस० एच० बेनसन (इंडिया) लि०, बम्बई।
4. मिस्टर एडवर्ड फील्डेन, अध्यक्ष और प्रबन्धक संचालक, जे० वाल्टर थोम्पसन (प्रा०) लि०, बम्बई।
5. श्री एम० एन० बनर्जी, प्रबन्ध संचालक, कलेरियन एड-वर्टाइजिंग सर्विसेज़ प्रा० लि०, कलकत्ता।
6. श्री एस० के० कूका, एअर इंडिया, बम्बई।
7. श्री पी० गुहा ठाकुरता, प्रचार मैनेजर, फिलिप्स इंडिया लि० कलकत्ता।
8. आल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडिटर्स कान्फ्रेंस नई दिल्ली के अध्यक्ष।
9. इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन, बम्बई के अध्यक्ष।
10. इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़पेपर्स सोसायटी, नई दिल्ली के अध्यक्ष।
11. श्री फ्रैंक मोरेस, प्रधान सम्पादक, इंडियन एक्सप्रैस, नई दिल्ली।
12. श्री रोमेश थापर, सम्पादक, सैमिनार, नई दिल्ली।
13. आल इंडिया मास्टर प्रिंटर्स फेडरेशन, बम्बई के अध्यक्ष।
14. श्री एन० जे० आर्देशीर, मैनेजिंग पार्टनर, मैसर्स वोल्टन फाइन आर्ट एण्ड लिथो वर्क्स, बम्बई।
15. श्री आर० के० लक्ष्मण, दि टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, बम्बई।
16. श्री अभिजित बरुआ, यूनिट 61, एडवर्टाइजिंग टोमस कुक बिल्डिंग, दादाभाई नारोजी रोड, बम्बई।
17. श्री पी० सान्याल, इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड, कलकत्ता।
18. डा० एम० एस० रंधावा, विशेष सचिव, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
19. श्री बी० सी० सान्याल, सचिव, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली।
20. श्री एस० एन० चिब, पर्यटन महानिदेशक, नई दिल्ली।
21. श्री एम० एल० भारद्वाज, निदेशक विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार, नई दिल्ली।

3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के इन्चार्ज उप-सचिव इस समिति के सचिव होंगे।

4. जब उपर्युक्त क्रम संख्या 1, 8, 9, 10 और 13 में उल्लिखित किसी संस्था का अध्यक्ष समिति की बैठक में स्वयं उपस्थित न हो सके तो उसका उपाध्यक्ष उपस्थित हो सकता है।

5. अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार और सदस्यों को सहयोजित कर सकें तथा अन्य सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्तियों को समिति की बैठकों में बुला सकें।

6. सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष होगा, लेकिन वे फिर से नियुक्त किए जा सकेंगे।

7. समिति की सदस्यता अवैतनिक होगी, लेकिन गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर संशोधित वित्त मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 6(26)ई० 4/59, दिनांक 5 सितम्बर, 1960 के अनुसार, सफ़र और दैनिक भत्ते के अधिकारी होंगे।

8. समिति की बैठक साधारणतया साल में एक बार होगी।

9. समिति अपनी कार्यविधि स्वयं तय करेगी।

10. समिति का कार्य विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार सम्बन्धी विषयों पर सरकार को सलाह देना होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

आदित्य नाथ झा, सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1965

सं० *W.B.* 21(16)/64—मुख्य पत्तनों के पत्तन और गोदी कामगरों के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड के लिए जिसकी नियुक्ति भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या W.B. 21(4)/64, तारीख 13 नवम्बर 1964 द्वारा की थी, उक्त संकल्प के विचारार्थ विषय द्वारा मजदूरों की अंतरिम सहायता संबंधी मांगों के बारे में अपनी सिफारिशें काम शुरू करने की तारीख से तीन माह के अन्दर भेजना अपेक्षित था। मजदूरी बोर्ड ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया है और उसने सरकार से प्रार्थना की है कि बोर्ड को अपनी

सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए एक माह का समय और दिया जाये। सरकार ने बोर्ड की यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसे आम सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० आर० सेठ, उप-सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 1965

सं० *W.B.* 17(13)/64—केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड ने, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार ने अपने संकल्प संख्या W.B. 17(2)/63, तारीख 25 फरवरी 1964 द्वारा की थी, समाचार प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों को अंतरिम सहायता मंजूर करने के लिए सिफारिशें कर दी हैं, जो कि परिशिष्ट में दी गई है।

2. इन सिफारिशों के बारे में मजदूरी बोर्ड ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण भी दिए हैं—

(1) अंतरिम सहायता के बारे मे बोर्ड की सिफारिशों की धारा 1 में निर्दिष्ट समाचार-पत्रों का वर्गीकरण श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

(2) उक्त सिफारिशों की धारा 3 में 50 रु० के हवाले का अभिप्राय समस्त मजदूरी से है जिसमें मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते शामिल हैं।

(3) प्रतिष्ठानों में अलग श्रेणी के ग्रुप, बहुविध और शृंखला समाचार-पत्रों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों को उन प्रतिष्ठानों में विभिन्न श्रेणियों के लिए सिफारिश की गई अंतरिम सहायता की राशि की औसत के बराबर अंतरिम सहायता दी जानी चाहिए।

(4) समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों मे अभिप्राय इस प्रकार के उन सभी कर्मचारियों से है जो कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1955 की धारा 2(च) के अन्तर्गत परिभाषित श्रमजीवी पत्रकार नही हैं।

3. सरकार ने बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने और संबंधित नियोजकों से उन्हें यथाशीघ्र लागू करने के लिए अनुरोध करने का निश्चय कर लिया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजस्व में प्रकाशित किया जाए।

पी० एम० मेनन, सचिव

परिशिष्ट

गैर-पत्रकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड

आल इंडिया न्यूजपेपर एम्प्लाइज फैडरेशन और दि फैडरेशन ऑफ प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया एम्प्लाइज एसोसियेशन ने समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों को अंतिम सहायता मंजूर करने के लिए मांग की है। गैर-पत्रकार कर्मचारियों की लगभग एक दर्जन एसोसियेशनो ने भी इस मांग को उठाया। भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या W.B. 17(4)/64 तारीख 7-10-1964 द्वारा विचारार्थ विषयों में संशोधन करके विचारार्थ विषयों में अंतरिम सहायता की मंजूरी की मांग पर विचार करने का विशिष्ट उल्लेख किया। कर्मचारियों के दावे का विस्तृत विवरण नियोजकों के केन्द्रीय संगठनों को टिप्पणियो के लिए भेजा गया। गैर-पत्रकार कर्मचारियों की श्रेणी और उनकी मजदूरी, समाचार-पत्र प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, आरक्षित निधि, ऋण, निवल लाभ आदि सम्बन्धी सूचना विभिन्न इकाइयों से श्रेणीवार स्वीकृत फार्म में मांगी गई। इस मामले पर अंतिम रूप से विचार बोर्ड द्वारा 12 दिसम्बर 1964 को बम्बई में हुई बैठक में किया गया। कीमतों में असामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और उद्योग की अदायगी-क्षमता पर सरसरी दृष्टि से विचार करने के बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया :—

प्रस्ताव

अंतरिम सहायता के प्रश्न पर बोर्ड सर्वसम्मति से फैसला करता है कि—

(1) समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों को निम्नलिखित आधार पर अंतरिम सहायता मंजूर की जानी चाहिए :—

(i) 'ए' और 'बी' श्रेणी समाचार-पत्रों के लिए 15 रु० प्रति मास की समान सहायता;

(ii) 'सी' श्रेणी समाचार-पत्रों के लिए 10 रु० प्रति मास की समान सहायता;

(iii) 'डी' श्रेणी समाचार-पत्रों के लिए 7.50 रु० प्रति मास की समान सहायता;

(iv) 'ई' और 'एफ' श्रेणी समाचार-पत्रों के लिए 5 रु० प्रति मास की समान सहायता।

(2) गैर-पत्रकार कर्मचारियों को यह अंतरिम सहायता 1 मई 1964 से दी जानी चाहिए।

(3) उपर्युक्त सिफारिशों के साथ यह शर्त है कि किसी भी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान में गैर-पत्रकार कर्मचारी को उक्त अंतरिम सहायता के साथ 50 रु० प्रति मास से कम नहीं मिलना चाहिए।

(4) यह अंतरिम सहायता सीमांत समंजन के साथ 750 रु० प्रति मास तक वेतन पाने वाले गैर-पत्रकार कर्मचारियों को दी जायेगी।

(5) यदि 1 मई 1964 को समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों और उनके कर्मचारियों में कोई समझौता विद्यमान हो जिसमें अंतरिम सहायता मंजूर की गई हो और यह व्यवस्था की गई हो कि मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के लागू होने के बाद उसमें समंजन किया जायेगा, तो वह समझौता कायम रहेगा। यदि पहले दी गई अंतरिम सहायता सिफारिश की गई अंतरिम सहायता से कम हो तो संबंधित गैर-पत्रकार कर्मचारियों को दोनों के बीच के अन्तर के बराबर राशि मिलेगी और यदि पहले दी गई अंतिम सहायता सिफारिश की गई सहायता से अधिक हो तो वे पहले मंजूर की गई अंतिम सहायता प्राप्त करते रहेंगे।

ह० (जी० के० शिंडे)
12-12-64

ह० (पी० ब्रह्मैया)
12-12-64

ह० (नरेन्द्र तिवारी)

ह० (उपेन्द्र आचार्य)

ह० (वी० आर० कुलकर्णी)
12-12-64

ह० (एस० के० कोल्हटकर)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th April 1965

No. 29-Pres./65.—Addendum—The following modifications are made to the Ordinances relating to the Territorial Army Decoration and Territorial Army Medal notified in this Secretariat Notification No. 84-Pres./64, dated the 4th December, 1964, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India of Saturday the 12th December, 1964 : - -

Territorial Army Decoration

After sub-para (b) of clause *Sixthly, insert* the following as sub-para (c) :—

"(c) Embodied service of a Territorial Army Commissioned Officer in India during the Emergency imposed since October 1962."

Territorial Army Medal

After sub-para (b) of clause *Seventhly, insert* the following as sub-para (c) :—

"(c) Embodied service in India during the Emergency imposed since October 1962."

CORRIGENDUM

The 14th April 1965

No. F.14(10)/65.—In the Notification of this Secretariat, No. 13-Pres./65, dated the 26th January 1965, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India for the week-ending January 30, 1965, on page 44, against Serial No. 5 :—

For the word 'Subhas' *read* 'Subhash'.

A. W. HOPCROFT, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

Education Division

New Delhi, the 7th April 1965

SUBJECT:—*Panel of Education—Reconstitution of*—

No. 1/4/62-Edu.—The Government of India is pleased to notify the nomination of Shri H. K. S. Lindsay of the Metal Box Co. of India Ltd on the Panel on Education from the date of issue of this Resolution.

2. Shri A. D. Ogilvie, President, Associated Chambers of Commerce of India, Andrew Yule Cole Ltd., 8-Clive Road, Calcutta-1 (West Bengal), who was appointed as a member of the Panel on Education *vide* Planning Commission Resolution No. 1/4/62-Edu. dated the 25th May, 1964 ceases to be a member of the Panel from 19th February, 1965.

ORDER

ORDERED that this Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of this Resolution be forwarded to all the members of the Panel on Education, all the State Governments, all the Ministries of the Government of India, the Cabinet Secretariat, the Department of Parliamentary Affairs the Prime Minister's Secretariat.

D. K. MALHOTRA, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Community Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th April, 1965

No. 30/11/62-Trg.II(T.III).—In partial modification of the Government of India, Ministry of Community Development and Cooperation Resolution No. 17/14/61-Trg.II, dated the 13th June, 1962, published in the Gazette of India Part I Section 1, dated the 30th June, 1962 and amendments thereto issued from time to time, the up-to-date composition and membership of the National Council of Study and Research in Community Development will be as under :—

President

Minister of Community Development and Cooperation.

Vice President

Deputy Minister of Community Development and Cooperation.

Members

1. Shri D. Basumatari.
2. Shri Brahm Perkash.
3. Shri G. Ramachandran.
4. Shri S. N. Dwivedy.
5. Shri Dayal Das Kurre.
6. Shrimati T. Lakshmikantamma.
7. Shri H. C. Mathur.
8. Prof H N Mukerji.
9. Shrimati Savitri Nigam.
10. Shri Rajeshwar Patel.
11. Prof. A. R Wadia.
12. Shri M Satyanarayana.
13. Shri Ram Narayan Choudhry.
14. Shri Dhirubhai Desai.
15. Dr. D. Ensminger.
16. Prof. B. N. Ganguli.
17. Shri E. P. Gopalan.
18. Prof. N. R. Malkani.
19. Shri S. N. Mozumdar
20. Shri B. Mukerji.
21. Shri T. S. Avinashilingam Chettiar.
22. Shri K. S. V. Raman.
23. Shri H. C. Linga Reddy
24. Shri Raghubir Sahai.
25. Prof. M. N. Srinivas.
26. Extension Commissioner, Department of Agriculture, Ministry of Food and Agriculture.
27. Shri P. M. Mathai, Director Industrial Cooperatives, Department of Industry, Ministry of Industry & Supply, New Delhi.
28. Dr. N Jungalwala, Deputy Director General of Health Services, Ministry of Health, New Delhi.
29. Col. S. G. Pendse, Director Training, Ministry of Labour and Employment, (Directorate General of Employment & Training), New Delhi.
30. Shri L. O. Joshi, Joint Secretary, Ministry of Education, New Delhi.
31. Shri S. C. Sen Gupta, Joint Secretary, Department of Social Security, New Delhi.
32. Shri N. V. Venkataraman, Financial Adviser to the Ministry of Community Development & Cooperation, Ministry of Finance, New Delhi.
33. Representative of the Planning Commission, New Delhi.
34. Shri N P. Chatterji, Joint Secretary, Department of Cooperation, Ministry of Community Development & Cooperation.
35. Principal, National Institute of Community Development, Rajendranagar, Hyderabad.
36. Dr. J. N. Khosla, Director, Indian Institute of Public Administration, New Delhi.
37. Shri S. K. Datta, Director, National Academy of Administration, Mussoorie.
38. Shri R. L. Gupta, Principal, Administrative Staff College, Hyderabad.
39. Shri V. S. Mathews, Commissioner Panchayati Raj and Secretary to Government, Community Development and Panchayati Raj Department, Orissa.
40. Shri M. A. Quaraishi, Commissioner and Secretary, Agriculture Production and Rural Development, Uttar Pradesh.
41. Shri N. Ananthapadmanabhan, Secretary, Rural Development and Local Administration Department, Madras.
42. Shri R. G. Salvi, Secretary, Rural Development Department, Maharashtra.
43. Shri R. Ghosh, Commissioner for Agriculture and Community Development & *Ex-Officio* Secretary to Government of West Bengal.

Member-Secretary

Shri I. D. N. Sahi, Joint Secretary (Trg.), Ministry of Community Development and Cooperation, Department of Community Development, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. R. DUBHASHI, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 14th April 1965

No. F.13(35)-W&M/62.—It is hereby notified for general information that, as from the 1st April, 1965, interest on 6½% Gold Bonds 1977, issued in terms of the Government of India, Ministry of Finance Notification No. F.13(35)-W&M/62, dated 5th November, 1962, will be at the rate of 7 per cent. per annum. All other terms and conditions relating to the Bonds remain unchanged.

By order of the President.

A. R. SHIRALI, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 9th April 1965

No. 3(1)/65-BOT.—In partial modification of the Government of India, Ministry of Commerce Resolution No. 3(1)/64-BOT dated the 6th July, 1964, as amended by Resolutions Nos. 3(1)/64-BOT dated the 7th August, 1964 and the 19th October, 1964 respectively, the Government have decided to increase the maximum number of members of the Board of Trade from 24 to 26, and to nominate the following Members of Parliament as members of the said Board :—

1. Shri Panampilli Govinda Menon;
2. Shri Radheshyam Ramkumar Morarka; and
3. Shri Babubhai Chinai.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Vice Chairman, Members of the Board of Trade, the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Ministers' Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Planning Commission, all Ministries of the Government of India and the State Governments in India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. S. JOSHI, Secy.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

(Department of Agriculture—I.C.A.R.)

New Delhi, the 12th April 1965

No. 10-3/65-Com.II.—In exercise of the powers conferred by clause 3(i) of the Resolution of the Government of India in the late Ministry of Agriculture No. F.43-11/48-Comm., dated the 21st May, 1949 (as amended from time to time), the Central Government is pleased to nominate Dr. M. S. Randhawa, Director General, Intensive Agricultural Areas and Special Secretary to the Government of India, Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture) and Vice-President, Indian Council of Agricultural Research as President of the Indian Central Arecanut Committee, with effect from the 3rd April, 1965 (A.N.) *vice* Shri A. D. Pandit.

N. K. DUTTA, Under Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT

(Transport Wing)

PORTS

RESOLUTIONS

New Delhi, the 9th April 1965

No. 9-PG(49)/63.—The Government of India have decided to associate the Naval Officer-in-Charge, Calcutta, with the Committee of Technical Officers set up to study the problems of navigation in the River Hooghly and hereby direct that the following amendment shall be made in the Ministry of Transport (Transport Wing's) Resolution No. 9-P.G(49)/63 dated the 26th September, 1964, namely :—

In paragraph 2 of the said Notification, entry 6 shall be renumbered as entry 7 and after entry 5, the following entry shall be inserted, namely :—

"7. Naval Officer-in-Charge, Calcutta. Member"

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments, the Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President and Planning Commission, for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and in the State Gazette for general information.

No. 9-PG(11)/65.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Calcutta for the year 1963-64. The following are the important features of the report :—

1. *Financial Position*

The Port Commissioners' revenue receipts for the year under review amounted to Rs. 1771.83 lakhs as against Rs. 1696.98 lakhs in the previous year. The increase in revenue receipts was mainly due to an increase of about 7% in the total traffic handled.

The expenditure during the year amounted to Rs. 1719.0 lakhs as against Rs. 1644.71 lakhs in the previous year. The year ended with a surplus of Rs. 52.73 lakhs in the revenue account. The increase in expenditure was mainly due to additional expenditure on establishment, stores, labour charges, electric light and power.

The amount available for appropriation in the Revenue Balance Account at the end of the year, composed of the year's surplus and the balance brought forward from the previous year, was Rs. 53.18 lakhs. Out of this amount, a sum of Rs. 53 lakhs was appropriated to the Capital Account as contribution from revenue, and the balance was carried forward to the next year.

In addition, for financing capital works, the Commissioners borrowed Rs. 100 lakhs during the year from Government and Rs. 310 lakhs in foreign exchange from the World Bank and also floated a 5 per cent 30-year loan of Rs. 100 lakhs.

The total balances in the various Revenue Reserve Funds as on the 31st March, 1964 amounted to Rs. 834.71 lakhs.

2. *Traffic*

The total imports and exports, which passed through the port during the year, was 6.028 million tonnes and 4.91 million tonnes, respectively, as against the corresponding import and export figures of 5.48 million tonnes and 4.723 million tonnes in the year 1962-63.

The tonnages of imports and exports of some of the important commodities handled during the year 1962-63 and 1963-64 are given below:—

Commodities	1962-63 (Million tonnes)	1963-64 (Million tonnes)
	IMPORTS	
Foodgrains	1·083	1·553
Salt	0·408	0·396
	EXPORTS	
Coal	2·151	1·974
Gunnies	1·078	1·104
Tea	0·182	0·163
Ores	0·550	0·790

3. *Port Railway*

The income derived from the Railway during the year amounted to Rs. 234.36 lakhs as against Rs. 249.82 lakhs in the previous year, which was inclusive of a sum of about Rs. 30 lakhs received from the trunk railways towards arrears of terminal and other charges payable up to the 31st March, 1962.

4. *Passenger Traffic*

The number of passengers who embarked from the Port during the year was 9,007. The number of passengers who disembarked was 4,414. The corresponding figures were 10,923 and 8,942 during 1962-63.

5. *Pilferages*

The various measures introduced in 1959-60 to minimise the incidence of pilferage in the Port continued to be effective.

6. *Shipping*

The number of the vessels that entered the port during the year was 1,828 as against 1,821 in the previous year. The ship with the deepest draft to enter the port was the S.S. "Wellesley Victory" drawing 27'-3" both forward and aft and the deepest draft ship to leave the Port was the S.S. "Janusha" drawing 26 ft. 9 in. both forward and aft.

The increase in the number of vessels during the year was less than what the additional traffic would have justified on past loading figures. This is an indication of the improvement in drafts during the year which enabled ships to carry more cargo. The conditions of the bars in the navigable river route to the Port were generally better than in the previous year. The governing bar which controlled the draft of ships during the year was below Diamond Harbour (Balari Bar) for 140 days and above Diamond Harbour for 226 days.

The total expenditure on dredging, including dredging of the navigable channel, berths, lock entrances and dock basin, amounted to Rs. 146.1 lakhs as against Rs. 156.1 lakhs during the previous year.

7. *Haldia Anchorage*

For the fifth year in succession, vessels importing foodgrains were worked at the Haldia Anchorage during the fair weather season from November, 1963, to February, 1964. In all 15 foodgrains vessels were worked at the anchorage during 1963-64. The deepest draft vessel to use the anchorage was the S.S. "Olivebank" which drew 29 ft. 10 in. The total quantity of foodgrains discharged at the anchorage was 60,414 tonnes.

8. *River Model Experiments*

All the items of technical equipment ordered were delivered and are in use. The Research Vessel 'Anusandhani', constructed in the U.K., was also put into commission. Systematic data are being collected, analysed and technical reports prepared.

Studies were carried out on the models at the Central water and Power Research Station, Poona. The main experiments undertaken during the year 1963-64 were:—

(i) feasibility study for the improvement of Ninan, Nurpur, Eastern Gut and Moyapur bars, and

(ii) experiments connected with the proposed crossings over the Hooghly River.

9. *Labour*

The labour situation in the Port during the year continued to be satisfactory.

The average rate of discharge per ship per day in the case of general imports, excluding foodgrains, was 434 tonnes as against 445 tonnes during the previous year. In the case of foodgrain imports, the average rate of discharge per ship per day worked out to 1,040 tonnes as against 1,372 tonnes during the previous year. The question of introducing an incentive scheme for increasing the output of labour on board ships is under the consideration of the Calcutta Dock Labour Board.

The average rate of loading per ship per day in the case of general exports, excluding coal and ores, was 642 tonnes as against 526 tonnes during the previous year.

In the case of coal exports, the average daily rate of loading per ship worked out to 1,036 tonnes as against 1,110.3 tonnes during the previous year. The average daily rate of loading in the case of ore vessels worked out to 1,511 tonnes as against 1,306 tonnes in the previous year.

The accommodation available in the transit sheds and yards was almost fully utilised during the year. There was no serious congestion in the Port at any time except for accumulation of cargo at heavy lift yards on account of difficulty in obtaining supply of special type railway wagons and delay in submission of documents by the importers and the clearing agents.

10. *Hooghly Pilotage*

The income from pilotage during the year was Rs. 56.20 lakhs and the expenditure Rs. 43.59 lakhs, with a surplus of Rs. 12.61 lakhs.

11. *Port Development*

The expenditure during the year on Capital works in progress amounted to Rs. 575.54 lakhs.

Considerable progress was made during the year on the various plan schemes including the construction of port craft, *viz.*, one scheme Despatch Vessel, one fire float, three launches, one grab dredger, two hopper barges, two water boats, two Pilot Vessels and a Survey Vessel. The acquisition of land for the construction of the new dock system at Haldia was also in progress during the year under review and certain preliminary works in connection with the Project were also taken in hand.

12. *Miscellaneous*

The new Hydraulic Study Department set up with the assistance and encouragement of the World Bank undertook a number of investigations during the year.

13. *Acknowledgement*

The Port Commissioners carried out useful work for another year despite difficult conditions and Government view with appreciation the work of the Port Commissioners during the year under review.

N. P. MATHUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 8th April 1965

No. DW.V.512(9)/64.—The following amendment shall be made in the Resolution of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power No. DW.V.512(9)/64 dated the 8th October 1964, constituting a Flood Control Board for Delhi and adjoining areas :

For the existing entry (4) under para 2 *viz.*,

"Chief Engineer, incharge of the Drainage Works of Delhi (yet to be appointed).

(Pending appointment of this officer Shri V. R. Vaish, Addl. Chief Engineer, Delhi Administration will act as Member).

Substitute

"Chief Engineer (Floods) Delhi Administration."

ORDER

ORDERED that the above amendment be published in the Gazette of India and copies communicated to all persons concerned.

ORDERED that a copy of the amendment be communicated to the State Governments of Punjab and Rajasthan with the request to them for publishing it in the State Gazettes for general information.

ORDERED also that a copy of the amendment be communicated to all the Ministries of the Government of India, the Planning Commission, the Prime Minister's Sectt., the Military Secretary to the President, the Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt., the Department of Parliamentary Affairs and the Comptroller and Auditor General of India.

K. G. R. IYER, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

RESOLUTION

New Delhi-1, the 19th April 1965

No. 41/9/63-Adv.—The Directorate of Advertising and Visual Publicity of the Ministry of Information and Broadcasting is responsible for the planning, designing and production of material for the publicity of the policies and activities of the Government of India. This is done through advertising, exhibitions, posters, folders, broad-sheets, calendars, diaries, cinema slides, hoardings, metallic tablets etc. The Government of India consider that it would be advantageous to have a machinery with persons and organizations whose knowledge, experience and advice would be helpful to the Directorate, for discussion and consultation on matters pertaining to the work of the Directorate of Advertising and Visual Publicity. It has, accordingly, been decided to reconstitute the Central Advisory Committee for Advertising and Visual Publicity. The Committee will consist of the Minister of Information and Broadcasting as Chairman and the Deputy Minister of Information and Broadcasting as Vice-Chairman.

2. In pursuance of the above decision, the Government of India are pleased to nominate the following persons as members of the Central Advisory Committee for advertising and Visual Publicity :—

(1) The President of the Advertising Agencies Association of India, Bombay.

(2) Shri B. B. Mundkur, Proprietor, Ulka Advertising, Bombay.

(3) Shri P. N. Sarma, Director, S. H. Benson (India) Ltd., Bombay.

(4) Mr. Edward J. Fielden, Chairman and Managing Director, J. Walter Thompson (Private) Ltd., Bombay.

(5) Shri S. N. Banerjee, Managing Director, Clarion Advertising Services Private Ltd., Calcutta.

(6) Shri S. K. Kooka, Air India, Bombay.

(7) Shri P. Guha-Thakurta, Publicity Manager, Philips India Ltd., Calcutta.

(8) The President, All-India Newspapers Editors Conference, New Delhi.

(9) The President, Indian Language Newspapers Association, Bombay.

(10) The President, Indian and Eastern Newspapers Society, New Delhi.

(11) Shri Frank Moraes, Editor-in-Chief, Indian Express, New Delhi.

(12) Shri Romesh Thaper, Editor, Seminar, New Delhi.

(13) The President, All India Master Printers' Federation, Bombay.

(14) Shri N. J. Ardeshir, Managing Partner, Messrs. Bolton Fine Art and Litho Works, Bombay.

(15) Shri R. K. Laxman, The Times of India, Bombay.

(16) Shri Abhijit Barua, Unit 61, Advertising, Tho's Cook Building, Dadabhai Naoroji Road, Bombay-1.

(17) Shri P. Sanyal, Indian Oxygen Ltd., Calcutta.

(18) Dr. M. S. Randhawa, Special Secretary, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi.

(19) Shri B. C. Sanyal, Secretary, Lalit Kala Akademi, New Delhi.

(20) Shri S. N. Chib, Director-General of Tourism, New Delhi.

(21) Shri M. L. Bhardwaj, Director of Advertising and Visual Publicity, New Delhi.

3. The Deputy Secretary incharge of the Directorate of Advertising and Visual Publicity in the Ministry of Information and Broadcasting will act as Secretary of the Committee.

4. A Vice-President of any of the organisations mentioned at S. Nos. 1, 8, 9, 10 and 13 above may attend a meeting of the Committee when the President of the said organisation is not in a position to attend himself.

5. The Chairman will have the power to co-opt additional members and to invite such officials and non-officials to attend the meetings as she considers appropriate.

6. The term of membership of Committee will be two years from the date of appointment, but the retiring members will be eligible for re-appointment.

7. Membership of the Committee will be honorary, but non-official members will be entitled to travelling allowance and daily allowance in accordance with the Ministry of Finance O.M. No. F.6(26)E-IV/59, dated the 5th September, 1960, as amended from time to time.

8. The Committee will ordinarily meet once a year.

9. The Committee will regulate its own proceedings.

10. The functions of the Committee will be to advise the Government on matters pertaining to advertising and Visual Publicity.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. N. JHA, Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 5th April 1965

WB-21(16)/64.—The Central Wage Board for Port and Dock Workers at major ports, set up by the Government of India by their Resolution No. WB-21(4)/64, dated the 13th November, 1964, was required by its terms of reference to submit its recommendations regarding the demands of labour in respect of interim relief, within three months from the date it started its work. The Wage Board has held discussions on this subject and it has requested Government to allow the Board one month more to finalise its recommendations. The Board's proposal has been accepted by Government. This is notified for general information.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. R. SETH, Dy. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 9th April 1965

*No. WB.*17(13)/64.—The Central Wage Board set up by the Central Government by their Resolution No. WB.17(2)/63, dated the 25th February, 1964, has made recommendations, as shown in the appendix, for grant of interim relief to the non-journalist employees of newspaper establishments.

2. The Wage Board has also given the following clarifications in regard to its recommendations :—

(1) The classification of newspapers referred to in clause 1 of the recommendations of the Board regarding interim relief is based on the recommendations of the Working Journalists Wage Committee.

(2) Reference to Rs. 50 in clause 3 of the said recommendations is to the consolidated wage—including basic wage, dearness allowance and other allowances.

(3) In the case of group, multiple and chain newspapers of different class in the same establishments the non-journalist employees should be given interim relief equal to the average of the quantum of the interim relief recommended for the different classes of newspapers in the said establishments.

(4) Non-journalist employees of the newspaper establishments would mean all those employees of such establishments who are not working journalists as defined under section 2(f) of Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

3. Government have decided to accept the recommendations of the Wage Board and to request the concerned employers to implement the same as early as possible.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. M. MENON, Secy.

APPENDIX

Central Wage Board for Non-Journalist Employees

The All India Newspaper Employees Federation and the Federation of Press Trust of India Employees Association have raised the demand for grant of interim relief to the Non-Journalist Employees of newspaper establishments. The demand was also raised by about a dozen associations of Non-Journalist employees. The Government of India in the Ministry of Labour and Employment modified the terms of reference *vide* Notification No. WB-17(4)/64 dated 7-10-64 specifically mentioning consideration of the demand for grant of interim relief as one of the terms of reference. The detailed statement of claim of the employees was forwarded to the Central Organisations of Employers for comments, information in an approved pro forma regarding category of non-journalist employees and their wages, financial position of the newspaper establishment, reserves, borrowings, net profit etc. was called for from various units classwise representing a fair cross section of the Industry. The matter was finally considered by the Board in its meeting held in Bombay on the 12th December, 1964. Taking into consideration the abnormal rise in the prices, and after cursorily examining the question of the capacity of the Industry to pay, the Board unanimously passed the following resolution :—

RESOLUTION

On the question of interim relief the Board unanimously resolved that :

(1) The interim relief on the following basis should be granted to non-Journalist employees of newspaper establishments :

(i) for 'A' and 'B' Class Newspapers a flat relief of Rs. 15 per month;

(ii) for 'C' Class Newspapers a flat relief of Rs. 10 per month;

(iii) for 'D' Class Newspapers a flat relief of Rs. 7.50 per month;

(iv) for 'E' and 'F' Class Newspapers a flat relief of Rs. 5 per month.

(2) This interim relief should be payable to Non-Journalist employees with effect from 1st May, 1964.

(3) The above recommendations are subject to the condition that in no newspaper establishments a Non-Journalist Employee, after taking into account the interim relief recommended above should get less than Rs. 50 per month.

(4) This interim relief shall be payable to Non-Journalist Employees drawing a salary up to Rs. 750 per month with marginal adjustments.

(5) If there be any agreement in force on the 1st May, 1964 between the Newspaper Establishments and their employees stipulating grant of interim relief, subject to adjustments after the recommendations of Wage Board are brought into force, those agreements shall stand. If the interim relief already granted is less than recommended above, the Non-Journalist Employees concerned shall get the difference of the two and if it is more than that recommended above, then they shall continue to get the interim relief already granted to them.

(Sd.) G. K. Shinde
12-12-64

(Sd.) P. Brahmayya
12-12-64

(Sd.) Narendra Tiwari

(Sd.) Upendra Acharya

(Sd.) S. Y. Kolhatkar

(Sd.) V. R. Kulkarni
12-12-64

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965